etc. These recommendations have already been taken note of by the Government both in the formulation of the National Policy on Education and the Programme of Action (as modified in 1992) and also while notifying the revised pay scales and emoluments of teachers from 1.1.1986.

मधुबनी, बिहार के स्वयंसेवी संगठनों को दी गयी सहायता

2525. **श्री रामदेव भंडारी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्रीं** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार के मधुबनी जिला में स्वयंसेवी संगठनों को उनके मंत्रालय द्वारा दी गयी सहायता का अद्यतन ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त संगठनों द्वारा निधियों के उपयोग की निगरानी के लिए क्या व्यवस्था है;

(ग) क्या वित्तीय अनियमिताओं के संबंध में उनके खिलाफ कोई शिकायतें मिली हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में की गयी कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (घ) इस मंत्रालय द्वारा स्वैच्छिक संगठनों, जिनमें बिहार के मधुबनी जिले में स्थित स्वैच्छिक संगठन भी शामिल हैं, को दी गई एक लाख से अधिक की सहायता के ब्यौरे इस मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्टों में उपलब्ध हैं जिन्हें बजट सत्र के दौरान माननीय संसद सदस्यों को परिचालित किया गया था और ये संसद पुस्तकालय में भी उपलब्ध हैं। शिक्षा विभाग ने उस जिले में विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों को क्रमश : 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान 8,35,419 रु॰, 6,94,535 रु॰ और 8,59,219 रु॰ की वित्तीय सहायता दी है। सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे किसी भी स्वैच्छिक संगठन को उपयोगिता प्रमाणपत्र और लेखा परीक्षित विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है, जिनकी आगे और कोई अनुदान देने पर विचार करने से पहले जांच की जाती है। विशेष शिकायतों के मामले में, मामले की जांच की जाती है और आरोपों की पुष्टि हो जाती है तो स्वैच्छिक संगठन के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय के शिक्षकों को अन्तरिम राहत

2526. **श्री गोविन्दराव आदिक : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली राज्य की भांति केन्द्रीय सरकार द्वारा केन्द्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और तिब्बती विद्यालयों के शिक्षकों को चट्टोपाध्याय समिति का प्रतिवेदन क्रियान्वित होने तक अन्तरित राहत स्वीकृत न करने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या इसे अब स्वीकार करने की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय समिति और केन्द्रीय तिब्बती स्कूल, प्रशासन भारत सरकार द्वारा पूर्णत: वित्त पोषित हैं, इन संगठनों के शिक्षकों को वेतन और भत्तों का भुगतान वेतनमानों के संबंध में भारत सरकार के निर्णय के अनुसार किया जाता है। सरकार ने इन संगठनों के शिक्षकों को कोई अंतरिम सहायता स्वीकृत करने का निर्णय नहीं लिया है।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन संबंधी समाचार

2527. **श्री राघवजी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 25 जुलाई, 1994 के नवभारत टाइम्स के दिल्ली महानगर संस्करण में प्रकाशित "केंद्रीय विद्यालय संगठन की स्थापना के उद्देश्यों पर सवालिया निशान" शीर्षक से छपे समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) जी, हां, यह समाचार मुख्यता दाखिलों, शिक्षा स्तरों में गिरावट और संगठन के कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों के बारे में है।

(ग) यह सच है कि केन्द्रीय विद्यालयों की संख्या में वृद्धि और उसके परिणामत: कर्मचारियों की संख्या में बढ़ोतरी के कारण और साथ ही केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए भारी मांग के कारण यह व्यवस्था बहुत दबाव में आ गई है। तथापि समाचार रिपोर्ट में उल्लिखित मामले तथ्यों से सिद्ध नहीं किए गए हैं।